प्रेस विज्ञप्ति

13.02.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक ऑफ इंडिया को **7 करोड़ रुपये (लगभग)** की अचल संपत्तियों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किया है। वैध दावेदार के रूप में, बैंक ऑफ इंडिया को उक्त संपत्तियों को वापस कर दिया गया है, जिससे एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 के तहत इसकी नीलामी बिक्री प्रक्रिया पूरी हो सके।

ईडी ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के अधिकारियों द्वारा की गई शिकायत के आधार पर सुधांशु कुमार हलदर, देबब्रत हलदर और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत बिधान नगर पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

जांच के दौरान, कोलकाता में विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली गई। इस मामले में 20.11 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क/फ्रीज की गई है, जिसमें आरोपी देबब्रत हलदर की अचल संपत्तियां भी शामिल हैं, जो बैंकों के पास गिरवी रखी गई थीं।

जांच के दौरान, इस घोटाले के मुख्य आरोपी और सरगना देवव्रत हलदर को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और देवव्रत हलदर और 13 अन्य आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की गई और एक पूरक अभियोजन शिकायत (एसपीसी) भी दायर की गई। पीसी और एसपीसी का संज्ञान भी उसी तारीख को माननीय विशेष न्यायालय द्वारा लिया गया है। इसके अलावा, माननीय विशेष न्यायालय ने आरोपी व्यक्तियों देवव्रत हलदर, उत्पल सरकार और राहुल पॉल को उद्घोषित अपराधी घोषित किया है।

इसके अलावा, बैंक ऑफ इंडिया ने निदेशालय से संपर्क कर बताया कि देबब्रत हलदर की दो अचल संपत्तियों पर 2.5 करोड़ रुपये और 2.47 करोड़ रुपये के दो ऋण हैं, जो एनपीए बन गए हैं और वर्तमान में आरोपी देबब्रत हलदर से 7 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि बकाया है। इसके अनुसरण में, बैंक ऑफ इंडिया ने पीएमएलए की धारा 8(8) के तहत एक आवेदन दायर किया और पीएओ संख्या 06/2023 के माध्यम से ईडी द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों की वापसी के लिए माननीय विशेष न्यायालय, सीबीआई-1, कलकत्ता के समक्ष अनुरोध किया, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया सुरक्षित लेनदार है।

माननीय विशेष न्यायालय, सीबीआई-1, कलकत्ता ने बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में संपत्तियों को छोड़ने/बहाल करने का आदेश दिया, ताकि वे अपनी नीलामी बिक्री की प्रक्रिया को पूरा कर सकें, जिसे उन्होंने एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 के तहत शुरू किया था। इसके अलावा, माननीय विशेष न्यायालय के आदेश के आधार पर, बैंक ऑफ इंडिया ने प्रवर्तन निदेशालय से बैंक को कुर्क की गई संपत्तियों (लगभग 7 करोड़ रुपये) को छोड़ने के लिए एनओसी जारी करने का अनुरोध किया। अनुपालन में, प्रवर्तन निदेशालय ने उन संपत्तियों के संबंध में बैंक ऑफ इंडिया को एनओसी जारी कर दी है, जिनमें बैंक ऑफ इंडिया संभावित दावेदार है।